AMENDMENTS IN THE ENVIRONMENT (PROTECTION) ACT, 1986.

PROPOSED AMENDMENTS TO ENVIRONMENT PROTECTION ACT, 1986:

- **Removal of Imprisonment:** The Ministry has proposed the removal of imprisonment as a penalty for the **"less severe"** contraventions.
  - It has proposed to replace imprisonment with monetary penalty for the "less severe" contraventions under the EPA.
- **Appointment of adjudication officer:** He would decide on a penalty in cases of environmental violations such as reports not being submitted or information not provided when demanded.
  - However, in case of serious violations which lead to grievous injury or loss of life, they shall be covered under the provision of the **Indian Penal Code, 1860.**
- **Environmental Protection Fund:** The amendments also propose the creation of an "Environmental Protection Fund" in which the amount of penalty will be remitted.

CURRENT PENAL PROVISION UNDER THE EPA 1986:

- It was enacted under **Article 253 of the Constitution,** the EPA came into force on November 19, 1986.
  - The Act establishes the framework for studying, planning, and implementing long-term requirements of environmental safety.
  - It lays down a system of speedy and adequate response to situations threatening the environment.
- **Penal Provision:** The Act currently says that violators will be punishable with imprisonment up to **five years** or with a fine up to **₹1 lakh, or with both.**
  - If the violation continues beyond a period of one year after the date of conviction, the offender can be punished with imprisonment for a term which may extend to seven years.

RATIONALE GOVERNING THE AMENDMENTS:

- The environment ministry had received **"suggestions"** to decriminalise existing provisions of the EPA to weed out **"fear of imprisonment for simple violations".**
- **Pending cases:**
  - An analysis by the **Centre for Science and Environment** found that Indian courts took between **9-33 years** to clear a backlog of cases for environmental violations.
  - Beginning **2018**, close to **45,000 cases were pending** trial and another 35,000 cases were added in that year.
  - More than **90% of cases** were pending trial in five of the seven environmental laws.

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में संशोधन

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 में प्रस्तावित संशोधन:

- **कारावास को हटाना:** मंत्रालय ने "कम गंभीर" उल्लंघनों के लिए दंड के रूप में कारावास को हटाने का प्रस्ताव किया है।
  - इसने ईपीए के तहत "कम गंभीर" उल्लंघनों के लिए कारावास को मौद्रिक दंड से बदलने का प्रस्ताव किया है।
- **न्यायनिर्णयन अधिकारी की नियुक्ति:** वह पर्यावरण के उल्लंघन जैसे रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किए जाने या मांगे जाने पर जानकारी प्रदान नहीं करने के मामलों में दंड का निर्णय करेगा।
  - हालांकि, गंभीर उल्लंघनों के मामले में जो गंभीर चोट या जीवन की हानि का कारण बनते हैं, उन्हें भारतीय दंड संहिता, 1860 के प्रावधान के तहत कवर किया जाएगा।
- **पर्यावरण संरक्षण कोष:** संशोधनों में एक "पर्यावरण संरक्षण कोष" बनाने का भी प्रस्ताव है जिसमें जुर्माने की राशि का भुगतान किया जाएगा।

ईपीए 1986 के तहत वर्तमान दंड प्रावधान:

- **इसे संविधान के अनुच्छेद 253 के** तहत अधिनियमित किया गया था, ईपीए 19 नवंबर, 1986 को लागू हुआ।
  - यह अधिनियम "पर्यावरण सुरक्षा की दीर्घकालिक आवश्यकताओं के अध्ययन, योजना और कार्यान्वयन के लिए ढांचा स्थापित करता है और पर्यावरण को खतरे में डालने वाली स्थितियों के लिए त्वरित और पर्याप्त प्रतिक्रिया की एक प्रणाली तैयार करता है।"
- **दंड प्रावधान:** वर्तमान में अधिनियम कहता है कि उल्लंघन करने वालों को **पांच साल तक की कैद या ₹1 लाख** तक का जुर्माना या **दोनों से दंडित किया जा सकता है।**
  - यदि उल्लंघन दोष सिद्ध होने की तिथि के बाद एक वर्ष की अवधि के बाद भी जारी रहता है, तो अपराधी को कारावास से दंडित किया जा सकता है, जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

संशोधनों को नियंत्रित करने वाला तर्क:

- पर्यावरण मंत्रालय को **"साधारण उल्लंघनों के लिए कारावास के डर"** को समाप्त करने के लिए ईपीए के मौजूदा प्रावधानों को अपराध से मुक्त करने के लिए **"सुझाव" प्राप्त हुए थे।**
- **लंबित मामले:**
  - **सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट** के एक विश्लेषण में पाया गया कि भारतीय अदालतों ने पर्यावरण उल्लंघन के मामलों के बैकलॉग को निपटाने में **9 से 33 साल का समय लिया।**
  - **2018** की शुरुआत में, लगभग **45,000 मामले लंबित थे** और उस वर्ष 35,000 अन्य मामले जोड़े गए थे।
  - सात पर्यावरण कानूनों में से पांच में **90%** से अधिक मामले लंबित थे।